माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी और एच. एस. बेदी के समक्ष

मास्टर हरि सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और,-उत्तरदाता।

1992 की सिविल रिट याचिका संख्या *6223*

23 दिसंबर, *1993*।

भारत का संविधान**,** *1950*-अनुच्छेद-आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ *(*रोकथाम*)* अधिनियम**,** *1987*-धारा ***19***-एफ. आई. आर. टाडा अधिनियम के तहत पंजीकृत-एफ. आई. आर.-एफ. आई. आर. को जांच स्तर पर रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका-रिट याचिका की स्थिरता।

अभिनिर्धारित किया कि टाडा अधिनियम का अर्थ यह नहीं लिया जा सकता है कि अनुच्छेद *226* और *227* के तहत न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों को बाहर कर दिया गया है।यह अधिनियम स्वयं संविधान का उत्पाद है।संविधान के तहत इस न्यायालय की शक्ति को नहीं छीन सकता और न ही छीन सकता है।अधिनियम की धारा *19* केवल तथ्यों और कानून दोनों पर नामित न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के अधिकार के बारे में बात करती है और यह प्रावधान करती है कि उपरोक्त निर्णय, सजा या निर्दिष्ट न्यायालय के आदेश के तहत किसी अन्य न्यायालय में कोई अपील या संशोधन नहीं होगा।यद्यपि उच्च न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण का अधिकार छीन लिया गया है, फिर भी अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *226* और*227* के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को छीनने का उल्लेख नहीं करता है।एक बार जब यह तथ्यों पर पाया जाता है कि संविधान के भाग आई. एच. द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आसन्न खतरा था, तो टाडा अधिनियम के प्रावधान उच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद *22*एफजे या *227* के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के रास्ते में नहीं आएंगे।बार में यह स्वीकार किया गया है कि इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद *323*-ए के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और संविधान में ही इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति में में, संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति निरंकुश बनी हुई है।

*(*पैरा *6)*

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक अभियोजन को निरस्त करने के प्रयोजनों के लिए संविधान के अनुच्छेद *226* या *227* के तहत न्यायालय की शक्ति सीमित है और इसका उपयोग केवल मौलिक या कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए उचित मामलों में किया जा सकता है या जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कथित अपराध की स्थापना के खिलाफ एक कानूनी बाधा थी जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो, पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है।इसी तरह, रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में शक्तियों की उपयोग नहीं किया जो सकता है या एक वादकारी को लागू करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः न्यायालय द्वारा समानांतर जांच की जा सकती है और जांच एजेंसी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने से रोका जा सकता है।एफ. आई. आर. को जाँच एजेंसी को उसके समर्थन में साक्ष्य एकत्र करने का अवसर दिए बिना रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।*(*पैरा *9)*

> याचिकाकर्ताओं की ओर से अजय लांबा ओटीडी एस "सरुला, अधिवक्ता और नवीन महाजन, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एस. सी. मोहंता आर.एस. चीमा।
>
> जे. के. सिब्बल, प्रतिवादीओं की ओर से अधिवक्ता सुश्री स्वर्णजीत कोहली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी

1. एफ. आई. आर. नं. *152,* पुलिस थाना सदर हिसार, अपराधों के लिए।

अधिनियम की धारा *3,4* और बी के तहत*)* (रोकथाम*)* अधिनियम, *1987* (इसके बाद के रूप में संदर्भित किया जाएगा*)* और शस्त्र अधिनियम की धारा *25* पर याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या *2* के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदविता के अवैध रूप से गर्भ धारण करने का आरोप है।सिविल रिट याचिका संख्या *1992* की*6223,1992* की *9975,1993* की *8321* और *1993* की *7130* के माध्यम से उपरोक्त एफ. आई. आर. को रद्द करने और प्रतिवादी को भारत के संविधान के अनुच्छेद *14,16,19* और *21* का उल्लघन करते हुए याचिकाकर्ताओं को परेशान करने से रोकने के लिए उचित निर्देश जारी करने का अनरोध किया गया है।यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों की कथित अवैध गिरफ्तारी और उत्पीड़न की स्वतत्र जांच का निर्देश दिया जाए।वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की जाती है कि एफ. आई. आर. की जांच एक स्वतत्र एजेंसी द्वारा की जाए और प्रतिवादी को उपरोक्त एफ. आई. आर., सलग्नक पी*/4* में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने से रोका जाए।

2. याचिकाकर्ता मास्टर हरि सिंह ने तर्क दिया है कि वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता और श्री देवी, लाल, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और उनके बेटे श्री ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व उप प्रधानमंत्री के सहयोगी हैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री।उन्होंने मई, *1991* में हुए चुनावों में प्रतिवादी संख्या *2* के खिलाफ आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का असफल होने का दावा किया।प्रतिवादी संख्या *2* को कांग्रेस पार्टी का नेता कहा जाता है जिसने कथित तौर पर अपने सभी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को विधानसभा चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोका था।कहा जाता है कि उसने शत्रुता और घृणा की कल्पना की थी

याचिकाकर्ता और उसका राजनीतिक दल अर्थात् समाजवादी जनता पार्टी।यह तर्क दिया जाता है कि *20* मई, *1991* को एफ. आई. आर. सं. *251* प्राप्त किया गया था।

आदमपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बलवंत सिंह के खिलाफ इस आरोप में मामला दर्ज किया गया था कि उनके पास अवैध हथियार पाए गए थे।उपरोक्त एफ. आई. आर. की जाँच के दौरान मास्टर हरि सिंह के दो करीबी रिश्तेदारों शेर सिंह और सुरेश को गिरफ्तार किया गया था।कहा जाता है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी आधार के गिरफ्तार करने के कई प्रयास किए गए और अंततः उसके खिलाफ एफ. आई. आर. संख्या *152* दर्ज की गई।और *11*मार्च को उनके अन्य राजनीतिक सहयोगी।*1992.*याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद *14,19* और *21* के तहत निहित अपने मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए नामित न्यायालय और इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या *2* ने अपनी राजनीतिक स्थिति का अंधाधुंध उपयोग किया और उच्च न्यायालय के विरोधियों को विभिन्न अपराधों में शामिल किया।विकास पार्टी के श्री ओ. पी. जिंदल के मामले को सनपोर्ट में याचिकाकर्ता के दावे और कथित रूप से हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री बी. वी. भजन लाल के राजनीतिक प्रतिशोध के शासन का हवाला दिया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता, उसके सहयोगियों और अन्य राजनीतिक विरोधियों को आपराधिक साजिशों में शामिल करने का उद्देश्य एक आतंक पैदा करना है। उद्देश्य यह कि भविष्य में किसी ने भी प्रतिवादी संख्या *2* के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की।एफ. आई. आर. का पंजीकरण भी प्रतिवादी संख्या *2* द्वारा कथितदुर्भावना का परिणाम होने का दावा किया जाता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वीकार किए गए तथ्यों पर भी-याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है।टाडा अधिनियम की धारा *5* के तहत जारी अधिसूचना के अधिकार को यांत्रिक रूप से और बिना दिमाग के लागू किए जारी किया गया है जिसे रद्द करने की आवश्यकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हरियाणा राज्य में और विशेष रूप से हिसार जिले में नाम के लायक कोई आतंकवादी अपराध नहीं किया गया है।पूरी जांच पर भारत के संविधान के अनुच्छेद *19* और *21* का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

3. आई. ओ. एफ. पी. प्रतिवादी संख्या *1* पर दायर टी. आई. टी. आई. एच. एल. रेप्लाइड में, इसने प्रस्तुत किया कि हरियाणा सरकार ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न का कोई कार्य नहीं किया है।हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि मास्टर हरि सिंह ने आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र से श्री भजन लाई के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा था और वास्तव में पराजित उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट प्राप्त किए थे।*1991* के एफ. आई. आर. सं. *251* का पंजीकरण स्वीकार किया जाता है लेकिन इस बात से इनकार किया जाता है कि उक्त एफ. आई. आर. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण या प्रतिवादी सं. *2* के कहने पर पंजीकृत किया गया था।एफ. आई. आर. सं. *152,* जिसे इस याचिका में रद्द करने की मांग की गई है, यह स्वीकार किया जाता है कि कुछ गुप्त जानकारी के आधार पर अपराध के कथित अपराध की तारीख से

लगभग नौ महीने बाद *11* मार्च, *1992* को दर्ज किया गया था।एफ. आई. आर. शुरू में याचिकाकर्ता हरि सिंह और उसके नौ अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में जांच के दौरान कई अन्य व्यक्ति अपराध में शामिल थे।ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से कई हथियार बरामद किए गए थे, जैसा कि लिखित बयान में बताया गया है।कहा जाता है कि सात और अभियुक्तों के संबंध में गिरफ्तारी के गैर-जमानतीय वारंट हिसार के इलाखा मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने अंतरिम अग्रिम प्राप्त किया था*?*इस न्यायालय से जमानत।जाँच के दौरान कई अभियुक्त व्यक्तियों ने स्वैच्छिक बयान दिए जिससे बरामदगी हुई और उनमें से कुछ के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *173* के तहत चालान पहले ही नामित न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं।एफ. आई. आर. संख्या *152* की जाँच के दौरान जाँच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए विभिन्न बयानों का एक संदर्भ यह दिखाने के लिए दिया गया है कि न्यायाधीश याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप बिना किसी आधार के थे और प्रतिवादी-राज्य को मामला दर्ज करने और इसकी जाँच करने के लिए उचित ठहराया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि टाडा अधिनियम की धारा *5* के तहत अधिसूचना उत्तर द्वारा जारी की गई थी -अपने दिमाग को पूरी तरह से लागू करने और पूरे राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ते खतरे को देखने के बाद, हिसार पंजाब राज्य का आदेश जिला होने के कारण, आतंकवादी बार-बार यहां हमला कर रहे हैं और दरगाहपुर बस नरसंहार और टोहाना हत्या जैसी घटनाएं *1*एडीए अधिनियम की धारा *5* के तहत अधिसूचना जारी करने को उचित ठहराती हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी या मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

4. संबंधित का आदेश उनके वैधानिक

   अपने शपथ पत्र में श्री भजन लाल ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने कई अन्य उम्मीदवारों के साथ आदमपुर विधानसभा का पिछला विधानसभा चुनाव उनके खिलाफ लड़ा था, जहां से उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया था।इस बात से इनकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या *2* ने कभी भी राजनीतिक शत्रुता या घृणा के कारण याचिकाकर्ता को राजनीतिक या आर्थिक रूप से समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है।प्रतिवादी संख्या *2* ने लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखने का दावा किया है और जहां तक याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुता के मामलों का संबंध है, अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या *2* ने कभी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दुर्भावना को स्वीकार नहीं किया था या उस कारण से उसे या उसके सहयोगियों को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास नहीं किया था।कथित तौर पर दुर्भावना के कारण मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया गया है।यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता और उसके अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं को आतंकित करने और बूथों पर कब्जा करने और प्रतिवादी संख्या *2* को हटाने के लिए एक गहरी साजिश रची गई थी, जिसे *1992* के एफ. आई.आर. संख्या *125* की जांच के दौरान पुष्ट किया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए उद्देश्य के साथ प्रेस बयान *(*अनुलग्नक पी*/8)* देने से इनकार कर दिया गया है।याचिकाकर्ता मास्टर हरि सिंह के आरोपों कि उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, का विशेष रूप से खंडन किया गया है और यह तर्क दिया गया है कि इस तरह के आरोप केवल प्रतिवादी को बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं।पुलिस द्वारा टाडा का उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भेदभाव से भी इनकार किया गया है, पुलिस अधिकारियों ने अभ्यास करने की सूचना दी है कानून के तहत कार्य जिनके साथ उक्त प्रतिवादी के पास कुछ भी नहीं था के साथ करें।याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने अपनी छवि खराब आदेश और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त आदेश के लिए याचिका में प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से घसीटा है।

5. श्री जिंदल और उनके सहयोगियों के बारे में आरोपों को जहां तक वर्तमान जालसाजों के फैसले का संबंध है, पूरी तरह से अप्रासंगिक बताया गया है।कहा जाता है कि ये आरोप श्री ओ. पी. जिंदल के कहने पर लगाए गए हैं और पुलिस ने कार्रवाई की है।

पाठ्यक्रम या कार्यवाही को टालते हुए विद्वान अधिवक्ता लॉर टने पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि इस याचिका का निपटान या प्रस्ताव के स्तर पर गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

(6) महत्वपूर्ण प्रश्न इस मामले में न्यायनिर्णयन की आवश्यकता वाली विधि यह है कि क्या उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* और *227*के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एफ. आई. आर. की कार्यवाही को रद्द कर सकता है या नहीं।यदि न्यायालय के पास राहत देने का अधिकार क्षेत्र है,जिसके लिए अनुरोध किया गया है, तो कौन से आधार हैं जिन पर राहत दी जा सकती है और ऐसी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं।यह आगे देखा जाना है कि मुख्य जांच से जुड़े कोई सहायक निर्देश दिए जा सकते हैं या नहीं।टाडा अधिनियम की धारा *5* के तहत अधिसूचना की संवैधानिकता की आगे जांच और निर्धारण करने की आवश्यकता है।

7. इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि विशेषाधिकार रिट असाधारण उपचार हैं जिन्हें असाधारण मामलों में लागू करने का इरादा है जिनमें सामान्य कानूनी उपचार पर्याप्त नहीं हैं।उपयुक्त मामलों में उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद *226* के अनुसार रिट जारी कर सकता है, जिसने इंग्लैंड की तरह विशेषाधिकार रिट जारी करने की शक्ति से अधिक दायरा बढ़ाया है।इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय विशेषाधिकार रिट जारी करने के अलावा विशेषाधिकार रिट के अलावा अन्य निर्देश और आदेश भी जारी कर सकता है और मामले की विशिष्ट और जटिल आवश्यकता को पूरा करने के लिए राहत को ढाल सकता है।यह कलकत्ता गैस कंपनी बनाम में आयोजित किया गया था।पश्चिम बंगाल राज्य *(1),* कि यह अनुच्छेद व्यापक रूप से लिखा गया है और मौलिक या कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के उद्देश्यों और किसी अन्य उद्देश्य के लिए अपनी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में उच्च न्यायालय पर कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगाता है।हालाँकि, उच्च न्यायालय की शक्ति हमेशा बोर्ड और मौलिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है जो विशेषाधिकार रिटों के अनुदान को विनियमित करते हैं।उस्मारिभाई दाऊदभाई मेमन और अन्य बनाम गुजरात राज्य *(2),* जिसमें याचिकाकर्ताओं पर टाडा अधिनियम के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर ध्यान दें और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः—

> *“* अधिनियम के प्रावधान किसी नागरिक के लिए अनुच्छेद *226* या अनुच्छेद *227* के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने या अनुच्छेद *32* के तहत एक याचिका द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए उपलब्ध संवैधानिक उपायों को नहीं छीनते हैं। उचित रिट, निर्देश या आदेश।यह आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए कि एक नागरिक हमेशा अनुच्छेद *226* या अनुच्छेद *227* के तहत उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है, या अनुच्छेद *32* के तहत इस न्यायालय को इस आधार पर अधिनियम या इसके प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे सकता है कि वे अनुच्छेद *14,21* और *22* के खिलाफ उल्लंघन करते हैं या इस आधार पर कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा *9 (1)* के तहत किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या अधिसूचना में निर्दिष्ट मामले या धारा या मामलों के समूह के लिए एक निर्दिष्ट न्यायालय का गठन करने वाली अधिसूचना शक्तियों के साथ धोखाधड़ी थी और इस प्रकार संवैधानिक रूप से अमान्य थी।

8. *“*टी. ए. ए. डी. ए. अधिनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनुच्छेद *226* और *227* के तहत न्यायालय की पारस्परिक शक्तियों को हटा दिया गया है।यह अधिनियम स्वयं संविधान का उत्पाद होने के कारण संविधान के तहत इस न्यायालय की शक्ति को नहीं छीनता है और न ही छीन सकता है।अधिनियम की धारा *19* केवल तथ्यों और कानून दोनों पर नामित न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के अधिकार के बारे में बात करती है और यह प्रावधान करती है कि किसी अन्य न्यायालय से कोई अपील या संशोधन नहीं होगा*;* किसी नामित न्यायालय के उपरोक्त निर्णय, सजा या आदेश से।यद्यपि उच्च न्यायालय में अपील या पुनरीक्षण का अधिकार छीन लिया गया है, फिर भी अधिनियम संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को छीनने का उल्लेख नहीं करता है।एक बार जब यह तथ्यों पर पाया जाता है कि संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आसन्न खतरा था, तो टाडा अधिनियम के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद *220* या *227* के तहत अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के रास्ते में नहीं आएंगे।बार में यह स्वीकार किया गया है कि इस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को छोड़कर

संविधान के अनुच्छेद *323*-ए के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और संविधान में ही इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति में में, संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति निरंकुश बनी हुई है।विद्वान अधिवक्ता श्री जे. के. सिब्बल ने भी यह स्वीकार किया है कि संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत इस न्यायालय को अधिनियम के तहत जारी किसी भी अधिनियम, नियम या आदेश की संवैधानिकता और उचित मामलों में कार्यपालिका की कार्रवाई की जांच करने की शक्ति है।एस. एम. डी. किरण पाशा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार *(3)*मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद *326* अनुच्छेद *32* में कुछ भी होने के बावजूद, उच्च न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें उपयुक्त मामले भी शामिल हैं। अंतरिम आदेश देने के अलावा, चाहे वह निषेधाज्ञा या स्थगन के माध्यम से या ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य तरीके से, भाग *III* द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी सरकारी निर्देश, आदेश या रिट के मामले।उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर भी विचार किया कि न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को किस स्तर पर लागू किया जा सकता है और अभिनिर्धारित किया जा सकता हैः—

" सवाल यह है कि अधिकार को किस स्तर पर लागू किया जा सकता है*?*क्या किसी नागरिक को अधिकार का उल्लंघन होने तक इंतजार करना पड़ता है*?*क्या वास्तव में उल्लंघन होने से पहले अधिकार को लागू करने का कोई तरीका नहीं है*?*क्या अधिकार का पालन करने के लिए राज्य की ओर से बाध्यता के दायित्व को अधिकार के उल्लंघन के बाद ही प्रभावी बनाया जा सकता है या दूसरे शब्दों में, क्या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को वास्तव में उल्लंघन होने से पहले लागू किया जा सकता है*?*जब किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का हनन किया जाएगा तो उसके लिए क्या उपाय बचा रहेगा*?*जब किसी अधिकार का उल्लंघन किया जाना बाकी है, लेकिन उल्लंघन की धमकी दी जाती है, तो नागरिक अधिकार की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख कर सकता है।अधिकार के संरक्षण को उल्लंघन के बाद इसकी बहाली या उपचार से अलग किया जाना है।जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है और राज्य सहित बाकी समाज उस अधिकार का उल्लंघन न करने के लिए मजबूर या बाध्य होता है, और यदि किसी ने इसका उल्लंघन करने की धमकी दी है या इसका उल्लंघन आसन्न है और जिस व्यक्ति के अधिकार को इतना खतरा है या इसका उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद *226* का इतना आसन्न है, तो क्या अदालत उन लोगों को प्रतिबंधित करके अपने अधिकार के पालन की रक्षा नहीं कर सकती थी जिन्होंने इसका उल्लंघन करने की धमकी दी थी जब तक कि अदालत कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं करती।हिंसा के बाद अनुच्छेद *226* का सहारा उल्लंघन के खिलाफ उपचार और अधिकार की बहाली के लिए है, जबकि हिंसा से पहले का संरक्षण कानून के तहत दायित्व या मजबूरी का अनिवार्य रूप से पालन करके उन सभी लोगों द्वारा अधिकार का उल्लंघन नहीं करना है-जो मजबूर कानून के लिए इतने बाध्य हैं, निश्चित रूप से केवल अधिक कार्यों के बाद ही कार्य कर सकते हैं।यदि उल्लंघन के प्रति प्रत्यक्ष कार्य पहले ही किए जा चुके हैं और वही, उस उल्लंघन की धमकी देने वाले व्यक्ति के संज्ञान में आया है और वह अनुच्छेद *226* के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाता है, जिसमें निकटवर्ती कार्रवाइयों का पर्याप्त विवरण दिया जाता है जो आसन्न रूप से अधिकार के उल्लंघन का कारण बन सकते हैं, तो क्या अदालत को उन लोगों से उपस्थित होने और कारण दिखाने के लिए उन कदमों को उठाने का आह्वान नहीं करना चाहिए जिन्हें उस अधिकार का उल्लंघन करने से रोका नहीं जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए अपनाया गया कि सह-कला निवारक न्यायाधीश के रूप में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है, जब तक कि उसके शासन का वास्तव में उल्लंघन नहीं किया जाता है,जहां अकेले वह एक रिट *1* बंदी प्रत्यक्षीकरण *Y. 11* के लिए याचिका दायर कर सकता है, संभावित उल्लंघनकर्ता को उल्लंघन की दिशा में कोई भी कदम उठाने से रोककर एक अधिकार के खतरे वाले आक्रमण को हटा दिया जाता है, अधिकार संरक्षित रहते हैं और इसके उल्लंघन के खिलाफ मजबूरी लागू की जाती है।यदि अधिकार का पहले ही उल्लंघन किया जा चुका है, तो जो बचा है वह इस तरह के उल्लंघन के खिलाफ और अधिकार की बहाली के लिए उपाय है।

8. जाँच एजेंसी को कानून द्वारा अधिकृत अध्याय *XII* के तहत कार्रवाई करने से वंचित करना।जहां सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन *(4)* मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तारीख को न्यायालय में कोई आरोप पत्र या शिकायत नहीं रखी गई थी और मामला केवल पुलिस द्वारा जांच के चरण में था, वहां न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग

करते हुए पुलिस की जांच की वैधानिक शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।उस मामले में इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* या *227* के तहत अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उक्त अधिनियम के तहत जारी किए गए किसी भी नियम, अधिसूचना या आदेश की संवैधानिकता और वैधता निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति है। इसके पास संविधान के भाग *III* में निहित नागरिक के मूल अधिकार को लागू करने के उद्देश्यों के लिए कार्यपालिका की किसी भी कार्रवाई की वैधता और संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति भी है।हालाँकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग मान्यता प्राप्त सीमाओं के अधीन है और इसका उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए।हालाँकि, आपराधिक अभियोजन को रद्द करने के उद्देश्यों के संविधान के अनुच्छेद *226* या *227* के तहत न्यायालय की शक्ति सीमित है और इसका उपयोग केवल मौलिक या कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित मामलों में किया जा सकता है या जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कथित अपराध के संबंध में आपराधिक कार्यवाही की स्थापना या जारी रखने के खिलाफ कानूनी बाधा थी, जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो, पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है।उच्च न्यायालय को इस बात की जांच शुरू करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय था या नहीं, जो विचारण न्यायालय या मजिस्ट्रेट का कार्य है।इसी तरह, रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में शक्तियों को एक वादकारी द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है या लागू करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः न्यायालय द्वारा जांच को रोक दिया जा सकता है और जांच एजेंसी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने से रोका जा सकता है:यह एक स्वस्थ प्रथा नहीं होगी यदि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को सभी मामलों में जांच के चरण में उच्च न्यायालय में इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करने के अनुरोध के साथ आने की अनुमति दी जाती है कि इस तथ्य के बावजूद कोई अपराध नहीं किया गया था कि जांच अभी तक शुरू नहीं हुई थी या लंबित थी।उच्च न्यायालय को जांच लंबित रहने के चरण में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए।केवल एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी भी मामले का फैसला नहीं किया जा सकता है।जिसका उद्देश्य आपराधिक जाँच की प्रक्रिया को गति देना है।जब जांच एजेंसी को निर्देश दिया जाता है तो उसे आरोपों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए बुलाया जाता है कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ क्या मामला बनाया गया था।एफ. आई. आर. को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है,जिससे जांच एजेंसी को उसके समर्थन में साक्ष्य एकत्र करने का अवसर मिल सके।संहिता की योजना।दंड प्रक्रिया की धारा इंगित करती है कि एफ. एल. आर. के पंजीकरण पर,पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को आरोपों की जांच और जांच करने की शक्ति है यदि उसके पास अपराध के होने पर संदेह करने का कारण है जिसके लिए वह धारा *156* के तहत ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की एक प्रति भेजने के बाद जांच करने के लिए सशक्त है।जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *161* के तहत गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति है। पी. सी., धारा *165* और *166* के तहत तलाशी लें, धारा *169* के तहत सबूत की कमी होने पर आरोपी को रिहा करें और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *173* के तहत जांच पूरी होने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पी. सी. किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है

कथित अपराध या कार्यवाही को रद्द करना।उस मामले की रिपोर्ट नई दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसमें मुंशी राम ने आरोप लगाया था कि वह इंद्राज सिंह और सुख लाल की बस के चालक के रूप में कार्यरत था। *13* जून, *1969* को उन्होंने मथुरा रोड पर एक देवी सिंह से बात करने के लिए बस रोकी, जिसने उन्हें और उनके साथियों को पास की एक दुकान पर शीतल पेय के लिए आमंत्रित किया।बस को बिना देखे छोड़कर वे उस दुकान की ओर बढ़े और इस बीच आरोपी व्यक्ति वाहन में सवार हो गए और पहले मुखबिर और उसके साथी द्वारा किए गए विरोध के बावजूद बस को भगा दिया।मुंशी राम ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *561*-ए के तहत याचिका दायर की थी। आर. सी. को चुनौती देना।रिपोर्ट के अनुसरण में कार्यवाही।सर्वोच्च

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या "ई" जेड को मांगी गई कार्यवाही अदालत में या अदालत के समक्ष लंबित थी, यह बताया गया कि याचिका दायर करने की तारीख को, वह अभी भी पुलिस द्वारा जाँच के चरण में था।इस विषय पर उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया:—

"यह सिद्धांत माजिर अहमद के मामले *71* इंड में प्रतिपादित किया गया था। अति.लो.अभि. *203-(*ए. आई. आर. *1945* पी. सी. *18-46* क्र. एल. जे. *113) (*उपर्युक्त*)* इस न्यायालय द्वारा एस. एन. बसाक के मामले *(1963) 2* एस. सी. आर. *52 = (*ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *447) 1963 (1)* सी.आर. में लागू किया गया था। एल. जे. *341) (*ऊपर*)*।इसमें पुलिस स्टेशन में इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि एस. एन. बसाक ने तीन अन्य लोगों के साथ दंड संहिता की धारा *420,120*-बी के साथ धारा *420* के तहत अपराध किए थे।पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।बसाक अभियुक्त ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।इसके बाद, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *439* और *561*-ए के तहत एक याचिका द्वारा उच्च न्यायालय का रुख किया और अनुरोध किया कि उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।जिस समय उन्होंने याचिका दायर की थी, उस समय किसी भी अदालत में कोई मामला लंबित नहीं था।उच्च न्यायालय ने पुलिस जाँच को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि "पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन *(*विशेष न्यायालय*)* अधिनियम, *1949* के तहत विचारण योग्य अपराध के संबंध में अध्याय *XIV* के तहत पुलिस को दी गई जाँच की वैधानिक शक्ति उपलब्ध नहीं है और ऐसा होने पर, संबंधित जाँच अधिकार क्षेत्र से बाहर है।*"* उस आदेश के खिलाफ, राज्य अनुच्छेद *134 (1) (*सी*)* के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया।अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने जे. एल. कपूर, जे. द्वारा से बोलते हुए कहाः

> *"*संज्ञेय अपराध की जाँच की शक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय *XIV* में निहित हैं।धारा *154* जो उस अध्याय में संज्ञेय अपराध में जानकारी से संबंधित है और धारा *156* ऐसे अपराधों में जांच से संबंधित है और इन खंडओं के तहत पुलिस को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना किसी भी कथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों में जांच करने का वैधानिक अधिकार है और जांच करने की पुलिस की इस वैधानिक शक्ति में धारा *439* के तहत या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा *561*-ए के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्ति के तहत हस्तक्षेप नहीं किया जा सकताहै।*"*

तत्काल मामले में बुनियादी तथ्य समान हैं।यहां भी, जब धारा *561*-ए के तहत याचिकाएं दायर की गई थीं, तब अदालत में आरोपी के खिलाफ कोई पुलिस चालान या आरोप-पत्र नहीं रखा गया था।विवादित कार्यवाही वे थीं जो पुलिस जाँच के दौरान की जा रही थीं।इसलिए, प्रथमदृष्टया बसाकके मामले में नियम आकर्षित किया जाएगा।*"*

आर. पी. कपूर के मामले *(*ऊपर*)* का उल्लेख करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने आगे कहाः—

> *"*यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप कथित अपराधों का गठन नहीं करते हैं,इसलिए उसके खिलाफ संस्था या कार्यवाही जारी रखने पर कोई कानूनी रोक नहीं है।यह आगे निर्धारित किया गया कि धारा *561*-ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय इस बात की जांच शुरू नहीं कर सकता कि मामले में साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं।*"*

8. पुलिस के साथ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभी भी लंबित जांच को जारी रखने या रद्द करने के संबंध में बार में प्रतिद्वंद्वी विवाद उठाए गए हैं।पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों की सराहना आदेश के लिए, एफ. आई. आर. पर एक नज़र डालना आवश्यक है जिसे रद्द आदेश की मांग की गई है।एफ. आई. आर. सं. *152,* संलग्नक पी*/4,* नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

> *"*इस समय एक विशेष मुखबिर ने पुलिस थाने में यह जानकारी दी है कि चौधरीवास निवासी मास्टर हरि सिंह पुत्र बैलू राम जाट, जो आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र द्वारा विधानसभा के उम्मीदवार थे, ने गांव चौधरीवास में *200* अवैध पिस्तौल लाने में कामयाबी हासिल की थी।चुनाव के समय आतंक पैदा करने और बूथ पर कब्जा करने के उद्देश्य से मेरठ के हिसार में वर्तमान में कार डीलर शेर सिंह पुत्र जगराम जाट, पुत्र चौधरीवास, सतबीर *(*एन> जवान पुत्र नाहला*)*।

इन पिस्तौलों को बाद में आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को वितरित किया गया।पिसाला पुत्र रामी लाल जाट पुत्र तेलांवाली, सेवक पुत्र जवान सिंह जाट, रमेश पुत्र अंश राम जाट पुत्र सलेमगढ़, उमेद सिंह इन पिस्तौलों को वितरित करने वालों में सूरत सिंह जाट निवासी जुगलान, दलीप पुत्र मोहब्बत जाट निवासी भेड़िया, पी. एस. सदर हिसार शामिल थे।अब भी उपरोक्त तरीके से आपूर्ति की गई अवैध पिस्तौल इनमें से कुछ व्यक्तियों के पास है और जब भी उन्हें मौका मिलेगा, वे आतंक पैदा करेंगे और इन अवैध हथियारों से माहौल खराब करेंगे।यदि इन व्यक्तियों पर छापे मारे जाते हैं और उनसे पूछताछ की जाती है, तो बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए जा सकते हैं और क्षेत्र को शांति भंग होने से बचाया जा सकता है।चूंकि जानकारी विश्वसनीय है और वही शस्त्र अधिनियम और टाडा अधिनियम की धाराओं के तहत अपराधों का खुलासा करती है, इसलिए यह मामला दर्ज किया गया है और आई इंस्पेक्टर एस. एच. ओ. एच. सी. सुबे सिंह *461*, एच. सी. पंजाब सिंह, *914*, सी. दलबीर सिंह *1219* के साथ सरकारी जीप नं. सतीश कुमार सी. *1244*, ए. एस. आई. दिलबाग सिंह और ए. एस. आई. जगदीप सिंह द्वारा संचालित एच. एन. एच. *3886* को अन्य अधिकारियों के साथ गांव सलेमगढ़ और जुगलान भेजा जा रहा है।

8. लिखित बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि घटना की तारीख से लगभग नौ महीने बाद मामला दर्ज किया गया था, फिर भी *11* लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से विभिन्न हथियार बरामद किए गए थे, जिसके लिए शस्त्र अधिनियम की धारा *25* और टाडा अधिनियम की धारा *5* के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. संख्या *152* में नामित कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ चालान पहले ही नामित न्यायालय में दायर किए जा चुके हैं।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं, जहाँ तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, ऐसा न हो कि यह किसी एक पक्षकार के लिए मामले को प्रभावित कर सकता है।हालाँकि, हम।यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता जहां तक एफ. आई. आर. को निरस्त करने का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद *226*और *227* के तहत हमारी शक्तियों के प्रयोग के लिए इसे एक दुर्लभ मामला बनाने की स्थिति में नहीं हैं।दुर्भावनापूर्ण आरोप इतने प्रबल नहीं हैं जो हमें इस स्तर पर पूरी जांच को रद्द करने के लिए राजी कर सकें।इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के साथ कथित रूप से सह-अभियुक्त व्यक्तियों से कुछ हथियारों की बरामदगी उन परिस्थितियों में से एक है जिसने हमें इस स्तर पर एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच किया है।ऊपर उल्लिखित परीक्षणों को लागू करते हुए, हम एफ. आई. आर. संख्या *152* में जांच को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद *226* और *227* के तहत अपनी शक्तियों को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं पाते हैं।की कथित कमजोरी आरोपों और मामले के अंतर्निहित दोषों की जांच की जानी चाहिए और पुलिस के पास सभी या किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को छोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं।

8. जहाँ तक टाडा अधिनियम की धारा *5* के प्रयोजनों के लिए धारा *2 (च)* के तहत अधिसूचना जारी करने का संबंध है, हमारे सामने यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि उक्त अधिसूचना असंवैधानिक या अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत थी। इस धारा के तहत राज्य को किसी विशेष क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति है या अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या इस धारा के अर्थ के भीतर राज्य का पूरा क्षेत्र या उसका कोई भी हिस्सा शामिल हो सकता है।न्यायालय इसका स्थान नहीं ले सकता है।किसी विशेष क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिनियम के तहत सशक्तअधिकारियों की संतुष्टि के लिए राय।

9. हालाँकि हमने एफ. आई. आर. को रद्द नहीं करने का विकल्प चुना है, फिर भी हमारी राय है कि यह एक उपयुक्त और उचित मामला है जिसमें याचिकाकर्ताओं के मूल अधिकार, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के उद्देश्यों के लिए निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी पर कोई उद्देश्य आरोपित किए बिना, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और कानून की गरिमा और गरिमा को बनाए रखने के लिए, हम वर्तमान मामले को एक उपयुक्त मामले के रूप में पाते हैं, जहां प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी के अपमान या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती के अधीन न करें, जब यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता विरोध में एक राजनीतिक दल से संबंधित हैं और याचिकाकर्ता मास्टर हरि सिंह ने

प्रतिवादी संख्या *2* के खिलाफ चुनाव लड़ा था।आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि किसी पक्ष को बचाव के लिए एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए और उसके मूल अधिकार के भंग की आशंका को कम करने की आशंका को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।यह प्रतिवादी के हित में भी हो सकता है कि वे वास्तविकता या प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह या संदेह छोड़े बिना मामले में उचित जांच करें।इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि जमानत को सजा के उपाय के रूप में नहीं रोका जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यह मांग करने के उद्देश्य से दी जाती है कि आरोपी पर मुकदमा चले और जांच या जांच में बाधा न आए।अभियुक्त व्यक्तियों को जाँच के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबंध लगाकर रोका जा सकता है।यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद *1* के तहत जमानत देने का सहारा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जहां मूल अधिकार के उल्लंघन की आशंका अधिक है, जैसा कि इस मामले में है, यह न्यायालय एक संविधान के तहत है -

नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उचित निर्देश देकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का राष्ट्रीय दायित्व।इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने और एक मिसाल नहीं बनाने के लिए हमें 'महाराष्ट्र राज्य बनाम अब्दुल हामिद हाजी मोहम्मद *(5)'* के रूप में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर आने के लिए राजी किया गया है।यह भी स्वीकार किया जाता है कि अधिकांश अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा चुकी है और उन्हें नामित अदालत में चुनौती दी जा चुकी है।इस विलंबित चरण में याचिकाकर्ताओं को घटना की कथित तिथि के ढाई साल से अधिक समय के बाद और उनके खिलाफ एफ. आई. आर. के पंजीकरण की तारीख से लगभग दो साल बाद जांच के कथित उत्पीड़न के अधीन करने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8. इन परिस्थितियों में रिट याचिकाओं का यह कहते हुए निपटारा किया जाता है कि इस स्तर पर टाडा अधिनियम की धारा *3,4* और *6* के तहत और शस्त्र अधिनियम की धारा *25* के तहत अपराधों के लिए हिसार के पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज *11* मार्च, *1992* के एफ. आई. आर. संख्या *152* को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है। तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं को टाडा और शस्त्र अधिनियमों के तहत अपराधों केलिए *11* मार्च, *1992* की एफ. आई. आर. संख्या *152* के संबंध में गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, तो उन्हें *5* लाख रुपये की राशि के जमानत बांड प्रस्तुत करने पर मुक्त कर दिया जाएगा। जाँचकर्ता या गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि के लिए उनके व्यक्तिगत बांड के साथ प्रत्येक *50,000*।सभी याचिकाकर्ता या उनमें से कोई भी, जैसा कि निर्देश दिया जाए, एफ. पूर्वाहन आर. की जांच के दौरान उपस्थित रहेगा। यदि आवश्यक हो तो उनकीउपस्थिति केवल कार्य घंटों के दौरान, यानी सुबह चार बजे से शाम चार बजे तक सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी याचिकाकर्ता किसी भी अभियोजन गवाह से संपर्क नहीं करेगा या जांच को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।याचिकाकर्ताओं में से कोई भी नामित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।पुनर्प्राप्ति, यदि कोई हो।किसी भी अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के परिणामस्वरूप**,** याचिकाकर्ता साक्ष्य अधिनियम की धारा *27*के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे। कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझसके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिकउद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्तरहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा